डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 फरवरी, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 फरवरी, 2025

| वर्ष 68 | अंक 18 | भोपाल | 16 फरवरी, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के हित में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र दिया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की

जल्द ही PACS भी कर सकेंगे एयरलाइंस टिकटों की बिक्री

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के गठन का विधेयक जल्द ही संसद से पारित होगा

विश्वविद्यालय बनने के बाद सहकारी क्षेत्र में आने वाले पेशेवरों को तकनीकी शिक्षा, एकाउंटिंग और प्रशासन संबंधी जानकारी व प्रशिक्षण मिल सकेगा

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 'सहकारी समितियों को सशक्तल करने के लिए की गई और वर्तमान में की जा रही पहलें' विषय पर सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल और श्री मुरलीधर मोहोल, समिति के सदस्यों, केन्द्रीय सहकारिता सचिव और सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने बैठक में सहकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी स्थापना के बाद से सहकारी समितियों को सशक्ता करने के लिए की गई और वर्तमान में की जा रही पहलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश भर के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के हित में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि दोनों संभव है।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश की आज़ादी के कुछ वर्षों बाद तक सहकारिता आंदोलन मजबूत स्थिति में था, लेकिन बाद में ज़्यादातर राज्योंमें यह कमजोर होता गया। उन्होंने कहा कि केन्द्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद हमने सबसे पहले राज्यों के साथ मिलकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का डेटाबेस बनाने का काम किया और दो लाख PACS के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब देश भर की सहकारी समितियों की क्षेत्रवार जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए कदम उठाये गये। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां PACS उपलब्ध नहीं हों।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि PACS को 'viable' बनाने के लिए बनाए गये बायलॉज़ को देश के लगभग सभी राज्यों ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि PACS को 20 से अधिक गतिविधियों से जोड़ा गया है और अब वे कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केन्द्र सहित अन्य सेवाएं प्रदान करना शुरू कर चुकी हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने मौजूदा बजट सत्र में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के गठन के लिए विधेयक पेश किया है और जल्द ही संसद से पारित होगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के गठन से सहकारी क्षेत्र में आने वाले पेशेवरों को तकनीकी शिक्षा, एकाउंटिंग और प्रशासन संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित मैनपावर उपलब्ध हो सकेगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) जैसी सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है, जिससे सहकारी क्षेत्र में निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादों और उन्नत बीजों को बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इन पहलों से आगामी कुछ वर्षों में सहकारी क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को कॉर्पोरेट सेक्टर के समान ही अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और आयकर विभाग के साथ मिलकर कॉर्पोरेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए टैक्स संरचना को एकसमान बनाने के लिए कदम उठाये हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि देश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े उद्यम कॉर्पोरेट जगत के साथ स्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करेंगे।

गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने परामर्शदात्री समिति को बताया कि सहकारिता से जुड़े राष्ट्रीय फेडरेशनों के त्वरित विकास के लिए कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अन्य फेडरेशनों के साथ रोडमैप बनाने पर कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि आज के समय में PACS रेलवे टिकटों की बुकिंग का काम कर रहे हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही PACS भी एयरलाइंस टिकटों की बिक्री कर सकेंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारिता केविकास में क्षेत्रीय असमानता को देखते हुए सरकार सभी राज्यों में एक समान संतुलित विकास लाने के लिए विशेष कदम उठा रही है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि 'सहकारिता में सहकार' (Cooperation Amongst Cooperatives) की पहल की गुजरात में व्यापक सफलता के बाद इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा।

बैठक में समिति के सदस्यों ने देश में सहकारी समितियों का सशक्तिकरण करने संबंधी मुद्दों पर अपने सुझाव दिए और सरकार द्वारा देश की सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की।

स्वच्छता से ही सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार : श्री सारंग

मंत्री श्री सारंग ने "स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता" अभियान की शुरूआत
पूरे प्रदेश के 10 हजार से अधिक सहकारी संस्थाओं के परिसरों में आगाज

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता के संदेश को आत्मसात कर अपने कार्य क्षेत्र को भी स्वच्छ बनायें। स्वच्छता से ही सकारात्मकता का संचार होता है। जिस प्रकार हम घर और घर के आसपास स्वच्छता रखते हैं, उसी प्रकार अपने कार्यस्थल पर साफ-सफाई के लिये हर माह एक नियत तारीख पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री श्री सारंग ने गुरुवार को अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में झाड़ू लगाकर साफ-सफाई कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के तहत चलाये जा रहे स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता अभियान की शुरूआत की। पूरे प्रदेश में 10 हजार से अधिक सहकारी संस्थाओं के परिसरों में यह अभियान एक साथ चलाया गया।

स्वभाव और संस्कारों में भी स्वच्छता जरूरी

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत सहकारिता का उन्नयन, विकास और सहकारिता के माध्यम से देश का नवनिर्माण करना ही लक्ष्य है। समाज और देश के नवनिर्माण के लिये सहकारिता के माध्यम से पूरी कार्य पद्धति को सार्थक और सकारात्मक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने स्वभाव और संस्कारों में भी स्वच्छता के साथ काम करने की बात कही। यह वर्ष सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण को समर्पित है।

सुव्यवस्थित रिकॉर्ड और उपयुक्त साफ-सफाई रखें

मंत्री श्री सारंग ने अपेक्स बैंक मख्यालय के भतल पर शाखा की साफ-सफाई एवं क्लियरिंग व रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि बिजली की वायरिंग आदि को सुव्यवस्थित करवाया जाये, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका न रहे। पुराने स्क्रेप का सामान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपलेखित कराया जाए। वे कभी भी मुख्यालय या किसी भी शाखा का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि उनके कक्ष में व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें और उपयुक्त साफ-सफाई हो। वाहन चालक अपने वाहन की एवं लिफ्टमैन लिफ्ट की साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य सभी की साफ-सफाई में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सहकारिता के प्रति लोगों को आकर्षित कर अधिक से अधिक इस अभियान से जोड़कर प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के निर्देशों के अनुरूप "अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025" के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

ग्राहक संतुष्टि पर प्रसन्नता जाहिर

मंत्री श्री सारंग ने शाखा में उपस्थित ग्राहकों से कर्मचारियों के व्यवहार और कार्य पद्धति को जाना। इस पर ग्राहकों से बैंक की सेवाएं उत्कृष्ट बताये जाने पर मंत्री श्री सारंग ने प्रसन्नता जाहिर की।

इस दौरान विधायक श्री अमर सिंह यादव, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री अरूण माथुर, श्री अम्बरीष वैद्य, श्री अरुण मिश्र, श्री संजय मोहन भटनागर, श्रीमती कृति सक्सेना, श्री एच.एस. वाघेला, श्री आर.एस.विश्वकर्मा, अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी श्री आर.एस. चंदेल, श्री के.टी. सज्जन, श्री आर.एस.मिश्रा, श्री अरविन्द बौद्ध, श्री समीर सक्सेना, श्री अजय देवड़ा के साथ अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

यह बजट विकास और कल्याण मूलक - मंत्री श्री सारंग

भोपाल : सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने केन्द्रीय बजट 2025-26 को "विकास और कल्याण मूलक" बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट "ज्ञान पर ध्यान" मंत्र को साकार करता है और देश के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग—गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

युवाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान

मंत्री श्री सारंग ने बजट को युवाओं और गरीबों के उज्ज्वल भविष्य की नींव बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल देश के समग्र विकास को गति देगी और भविष्य की पीढ़ियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार को इस दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

आर्थिक अनुशासन और समावेशी विकास

मंत्री श्री सारंग ने बजट को संतुलित और समावेशी बताते हुए कहा कि यह देश के आर्थिक अनुशासन को बनाए रखते हुए विकास की गति को तेज करेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

नई तकनीक और सहकारिता से होगा किसानों का उत्थान : मंत्री श्री सारंग

एफपीओ को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी : मंत्री श्री कुशवाह
कृषि क्रांति 2025 एफपीओ कॉन्क्लेव में दिये गये कृषि रत्न सम्मान

भोपाल :सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि नई तकनीक और सहकारिता से किसानों का उत्थान होगा। खेत, खलियान और किसान सरकार की प्राथमिकता है। विकसित भारत की परिकल्पना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन तीनों के उन्नयन और उत्थान की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने से ही देश विकसित हो पाएगा, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इससे प्रोडक्शन में रिकॉर्ड दर्ज किया और 7 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला। मंत्री श्री सारंग सोमवार को नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कृषि क्रांति 2025 एफपीओ कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह भी उपस्थित थे।

मंत्री से सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि को उन्नत बनाने हर क्षेत्र में काम किया है। किसानों को फसल का सही मूल्य मिल सके, समय पर उपार्जन सहित खाद, बीज, पानी मिल सके इसका ध्यान रखा गया है। अब किसान को व्यवसायी के रूप में परिवर्तन करना सरकार का मुख्य काम है और यह केवल सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसानों को एफपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती से जोड़ना होगा, जिससे उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एफपीओ को किसानों को जागरूक करना होगा। सरकार एफपीओ को हर तरह की सुविधा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष- 2025 में हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से सहकार सभा होगी। इसमें भी एफपीओ जोड़कर किसान को सरकार से समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं।

एफपीओ कॉन्क्लेव से सहकार की भावना मजबूत होगी

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि एफपीओ कॉन्क्लेव से सहकार की भावना मजबूत होगी। सहकारिता मानव स्वभाव का मूलभूत आधार है.सहकारिता के बिना इस समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आज के समय में सहकारिता के माध्यम से नई-नई तकनीक से जोड़ना, फूड प्रोसेसिंग आदि पर काम करना, खेती में वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता हैं, जिससे अच्छे परिणाम आए इसमें सरकार सहायता देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ समाज जनता सहकारी संस्थाओं एफपीओ सब मिलकर काम करें, इस दिशा में कार्य करने के लिए सरकार प्रदेश के उन्नयन के लिए तत्पर है।

खाद्य प्र-संस्करण से किसानों की आत्मनिर्भरता

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि एफपीओ और खाद्य प्र-संस्करण को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी है। उन्होंने फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि"राज्य सरकार जल्द ही एक विशाल फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें किसानों, उद्यमियों, क्रेताओं और विक्रेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा।"

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि किसान की आय दोगुना करने के लिये चल रहे कार्यों से फसलों का मूल्य अच्छा मिल सकेगा और उसका संवर्धन हो सकेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश मसाला उद्योग में एक नम्बर पर है। सरकार अलग-अलग योजनाओं से किसानों की उत्थान की दिशा में काम कर रही है। उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर नये किसानों को रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विकसित कृषि के लिये नई खेती से जुड़ना होगा, इसके लिये किसान उद्यानिकी से भी जुड़े।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कई देश जैविक खेती में आगे बढ़ रहे हैं। जैविक खेती से पैदा होने वाली फसल से दुष्प्रभाव नहीं होता। इससे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्र-संस्करण के क्षेत्र में कोई भी परियोजना व्यक्ति या संस्था लगाती है तो 35 प्रतिशत अनुदान सरकार दे रही है। साथ ही अनेक योजनाओं और कृषि उपकरण में भी सरकार अनुदान दे रही है।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्र खराबी पर मैकेनिक एवं उपकरण स्टोर, प्रबंधन आदि आवश्यक है। इस पर भी ध्यान देकर आगे बढ़ा जा सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से किसानों को मदद मिलेगी और उचित दाम से किसान संबल होंगे।

'कृषि क्रांति : एफपीओ कॉन्क्लेव' में अधिकारियों, विशेषज्ञों, निर्यातकों, क्रेताओं और तकनीकी प्रदाताओं ने एफपीओ के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य एफपीओ को खाद्य प्र-संस्करण और निर्यात योग्य उत्पाद तैयार करने में सक्षम बनाना था। कॉन्क्लेव का आयोजन भूमिशा ऑर्गेनिक, डिक्की और सर्च एंड रिसर्च डेवपलमेंट सोयायटी ने किया।

विशेषज्ञों के विचार एवं मार्गदर्शन

कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सुश्री प्रतिभा तिवारी, डिक्की के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरवैया और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. मोनिका जैन ने भी कॉन्क्लेव में विचार रखे। कॉन्क्लेव में सॉलिडरिडाड के जनरल मैनेजर सुरेश मोटवानी, एसबीआई के एजीएम श्री शशांक कुमार, एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के श्री अरुणाभ दुबे, सी-मैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आलोक कृष्णा और उद्यानिकी विभाग के अपर संचालक श्री कमल सिंह किरार प्रमुख थे।

कृषि रत्न सम्मान एवं सहयोग

कार्यक्रम में 8 एफपीओ और 2 किसानों को 'कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया। इनका सम्मान पत्र बांस से तैयार किया गया था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 2 एफपीओ को 28.5 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई, जिसकी पहली किश्त सहकारिता मंत्री श्री सारंग और एनएसडीसी की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री इंद्रजीत कौर ने प्रदान की। इस मौके पर लक्ष्य प्राप्ति के सूत्र पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

कृषकों के भुगतान को आसान बनाने के लिये ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं समस्याओं के निराकरण के लिये प्रतिबद्ध है। किसानों की उपज का भुगतान आसान बनाने के लिये प्रदेश में ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है। कृषकों को इस प्रणाली से जोड़कर प्रत्येक भुगतान की एंट्री ई-अनुज्ञा पोर्टल पर हो रही है। व्यापारियों द्वारा इस प्रणाली का इस्तेमाल कर क्रय की गई कृषि उपज के परिवहन के लिये गेट पास बनाये जा रहे हैं। रिकॉर्ड संधारण में इस प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है।

ई-मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। मंडियों में इस योजना के लागू होने से मैनुअली संधारित रिकॉर्ड धीर-धीरे समाप्त हो रहा है। ई-मंडी योजना मंडी प्रांगण के अंदर कृषकों को प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करने की प्रक्रिया है। योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है।

ड्रोन तकनीक से फसलों के उत्पादन में होगी वृद्धि

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है। ड्रोन तकनीक से खेतों की सटीक स्थिति का मूल्यांकन हो सकेगा, जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। फसलों में बीमारी, कीट और पर्यावरणीय प्रभावों की शीघ्र पहचान की जा सकेगी। इससे जल का कुशल उपयोग, जल संरक्षण में वृद्धि और सिंचाई लागत में कमी आएगी। ड्रोन से कृषि उत्पादकता और फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। किसानों को ड्रोन प्रौद्योगिकी से नई कृषि पद्धतियों का लाभ मिलेगा।

सहकारिता वर्ष-2025 में हर माह होगा सहकारिता संबंधी भव्य आयोजन : मंत्री श्री सारंग

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय वार्षिक कैलेण्डर संबंधी हुई बैठक

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता वर्ष-2025 में राज्य स्तर पर हर माह सहकारिता संबंधी एक भव्य आयोजन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और सहकारिता विभाग से जुड़े संबंधित विभागों के केन्द्रीय मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हर माह कार्यक्रम होंगे। मंत्री श्री सारंग मंत्रालय में सहकारिता वर्ष-2025 के लिये राज्य स्तर पर किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे।

देश के सहकारी आंदोलन से जुड़े प्रख्यात लोगों को भी जोड़ें

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इन कार्यक्रमों में देशभर के सहकारी आंदोलन से प्रख्यात जुड़े लोगों को भी जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि इस दौरान अन्य राज्य के दलों को आमंत्रित कर मध्यप्रदेश में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य वाली संस्थाओं का भ्रमण एवं प्रदर्शन करवाया जाये। इसके लिये जो स्टडी ग्रुप आयें, तो उनके साथ मध्यप्रदेश का एक दल उन्हें प्रदेश में किये गये नवाचार और उत्कृष्ट कार्य के बारे में बखूबी जानकारी दे।

ग्राम पंचायतों में भी सहकारिता से जुड़ी गतिविधियाँ हों संचालित

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य स्तर के साथ हर जिले और ग्राम पंचायतों में भी सहकारिता से जुड़ी गतिविधियाँ संचालित हों। हर जिले में ग्रुप बनाये जायें और ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाये। साथ ही सहकार और सहकारिता के बारे में हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों को जानकारी दी जाये। हर गाँव में सहकार सभा जैसे कार्यक्रम हों। इसमें सरपंच और जन-प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये।

सहकारी बैंकों में उपलब्ध सुविधाओं के लिये हो जन-जागरूकता

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी बैंकों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जन-जागरण किया जाये। बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिये अभियान चलाया जाये। कृषक और आमजन सहकारी बैंक से जुड़ें, इस पर फोकस किया जाये। वार्षिक कैलेण्डर में सहकारी मंथन, सहकारी सम्मेलन, ग्राहक जागरूकता सम्मेलन, पौध-रोपण अभियान, टर्म-लोन वितरण, नवीन केसीसी स्वीकृति, अमानत संग्रहण, विचार संगोष्ठी, सर्वोत्तम कार्य करने वालों का सम्मान जैसी गतिविधियों का भी समावेश किया जाये।

बैठक में प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक कुमार सिंह, पंजीयक सहकारिता श्री मनोज पुष्प, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, प्रबंध संचालक सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक आवास संघ श्री रमाशंकर विश्वकर्मा, दुग्ध संघ के डॉ. दुरवार, संयुक्त पंजीयक श्री अमरीश वैद्य, संयुक्त पंजीयक वनोपज संघ श्री बी.पी. सिंह, ओएसडी अपेक्स बैंक सुश्री कृति सक्सेना, सचिव मत्स्य महासंघ श्री यतीश त्रिपाठी और उप सचिव श्री हितेन्द्रह सिंह बघेला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सभी सेक्टर को एक साथ जोड़ने का माध्यम सहकारिता : सहकारिता मंत्री

राज्य ऋण संगोष्ठी में हुआ सराहनीय प्रदर्शन करने वाले हितग्राहियों का विशेष सम्मान

भोपाल :सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि किसी भी देश के उन्नयन, विकास और जनता के कल्याण के लिये अर्थ-व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि जहाँ व्यक्ति है, वहाँ अर्थ है और जहाँ अर्थ है वहाँ अर्थ-व्यवस्था। विकसित भारत निर्माण की परिकल्पना के लिये अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये संकल्प के साथ प्लानिंग करनी होगी। सभी अर्थ-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये लक्ष्य के साथ अपने-अपने प्रकल्प पर काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर को एक साथ जोड़ने का माध्यम सहकारिता है। मंत्री श्री सारंग गुरूवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राज्य ऋण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश की हर पंचायत पर स्थापित होगा पैक्स

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि ऋण देना और समय पर वापस लेना अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। उन्होंने कहा कि एक जैसे सेक्टर के लोग लगातार संवाद करें। समन्वय और परिस्थिति को जांचते हर तीन माह में एक-दूसरे की अपेक्षाओं पर काम करने से और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता का महत्वपूर्ण स्तम्भ संस्कार है। पारदर्शिता और कम्प्यूटराइजेशन के साथ अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये सुधार आवश्यक है। सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये मध्यप्रदेश की हर पंचायत पर पैक्स स्थापित किये जायेंगे।

अर्थ-व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिये मध्यप्रदेश दृढ़ संकल्पित

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक में सहकारी आन्दोलन के माध्यम से नये रोजगार के अवसर सृजित कर उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिये काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाचार विंग के माध्यम से नित नये आयाम के द्वार खोले जा रहे हैं। प्रदेश में समितियों का फेडरेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कॉर्पोरेट कल्चर को अपना कर बौद्धिक कुशलता और रोजमर्रा की कार्यप्रणाली पर काम किया जा रहा है। अर्थ-व्यवस्था के निर्माण और विकास के लिये मध्यप्रदेश दृढ़ संकल्पित है। देश को तीसरे नंबर की इकॉनोमी वाला बनाने के लिये मध्यप्रदेश जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है।

मंत्री श्री सारंग ने राज्य फोकस पेपर 2025-26 पुस्तिका और सफल नवाचार की कहानियों पर आधारित "नैब-पहलें" का विमोचन किया। संगोष्ठी में सहकारी संस्थाओं को नाबार्ड की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति-पत्र वितरण और राज्य में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले हितग्राहियों का विशेष सम्मान किया गया।

संगोष्ठी को आरबीआई की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री रेखा चन्दनवेली, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री चन्द्रशेखर शर्मा और नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सुश्री सी. सरस्वती ने भी विचार व्यक्त किये। इस मौके पर सहकारिता आयुक्त श्री मनोज पुष्प, एस.एल.बी.सी. के डीजीएम श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित थे। संगोष्ठी में राज्य फोकस पेपर 2025-26 पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

सर्वोत्तम आचरण बने जिला सहकारी बैंक की पहचान : मंत्री श्री सारंग

समन्वय भवन में जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सर्वोत्तम आचरण जिला सहकारी बैंक की पहचान बने। उसके अच्छे कार्यों की मार्केटिंग की जाये। हर बैंक के कर्मचारियों की आचरण और व्यवहार की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाये। उन्होंने कहा कि नवाचार और अच्छा काम करने के लिये बैंक के हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो तथा साल के अंत में उत्कृष्ट कर्मी को सम्मानित भी किया जाये। मंत्री श्री सारंग शनिवार को अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सहकारी बैंक के सुदृढ़ीकरण पर दें ध्यान

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी बैंकों को अपनी साख के लिये काम करना होगा। उसमें पारदर्शिता लानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि बैंक में डिपॉजिट पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बैंक को वसूली आदि नियमित कार्य के साथ सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना होगा। डिपॉजिट, टर्म लोन, सेफ लोन देने के मामलों काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक के कर्मचारियों का कार्य-व्यवहार, संवाद और बैंक का माहौल सकारात्मक हो। काम को चैलेन्ज के रूप में लें। कमजोर बैंकों को अच्छे पर लाने और अच्छे को कमजोर न होने देने की दिशा में काम कर आगे बढ़ना होगा।

सहकारी बैंक प्रोफेशनल एप्रोच के साथ करें काम

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि डिफाल्ट किसानों के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करवायें, ताकि वे लोन चुकाने के लिये उन्हें मोटिवेट कर सकें। कलेक्टर के साथ राजस्व अमले से भी संवाद स्थापित करें, जिससे को-आर्डिनेशन और को-आपरेशन के जरिए सहकारी बैंक से सरकारी अमला भी जुड़ सके। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बैंक प्रोफेशनल एप्रोच के साथ काम करें। हरेक पेक्स 2-3 कर्मियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाये। उन्होंने कहा कि 2-3 माह में वसूली के प्रकरणों का निराकरण करें। इसके लिये लम्बी प्रक्रिया न हो, काम को स्पीड-अप करें। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कमजोर पेक्स के उन्नयन एवं उत्थान के लिये काम किया जाये। वर्गीकरण कर उसे मजबूत बनाया जाये। प्रत्येक पंचायत में पेक्स हो, नई पेक्स को बहुउद्देशीय बनाया जाये। सहकारिता से जुड़े विभागों का सहयोग लिया जाये। उन्होंने कहा कि नई सोसायटी के लिये फेडरेशन भी बनाया जा रहा है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकार-सभा के माध्यम से कॉलेजों में सहकारिता को लेकर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हों। बैंकों में 100 प्रतिशत ऑडिट हों, एक भी बैकलॉक नहीं रहे। हरेक बैंक के नवाचार एवं अच्छे कामों का प्रचार-प्रसार हो, इसके लिये व्हाटसएप ग्रुप के माध्यम से सफलता की कहानी मुख्यालय पर प्रेषित की जाये, ताकि सोशल- मीडिया जैसे माध्यम से लोग अवगत हों।

कृषि विकास को अग्रणीय बनाने में सहकारी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका

अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल ने कहा कि कृषि विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिये सहकारी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिये पेक्स को मजबूत कर बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। पेक्स को मल्टीपर्पस बनाया जाना होगा। बिजनेस अवसर के डेवलपमेंट प्लान डिजाइन करने होंगे। माइक्रो एटीएम का उपयोग बढ़ाया जाना होगा। सहकारी बैंक अपनी सर्विसेस बढ़ाये जिससे आसान ट्रॉजेक्शन से ग्राहकों को सुविधा हो।

आयुक्त सहकारिता व पंजीयक श्री मनोज पुष्प ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बैठक हर माह होती है और डिस्ट्रिक लेवल की मॉनिटरिंग के साथ क्रेडिट मूवमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर सहकारिता मंत्री की मंशानुरूप प्रत्येक पंचायत को समिति का सदस्य बनायें एवं "सहकार-सभा" का हर पंचायत में आयोजन कर जनप्रतिनिधियों को इनमें आमंत्रित कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाये। इससे अधिक से अधिक लोगों का सहकारी बैंकों से जुड़ाव होगा और केंद्र शासन का "सहकार से समृद्धि" का संकल्प भी क्रियान्वित होगा।

उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि पैक्स से वही किसान खाद ले सकेगा जो सदस्य होगा। उप महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल ने माइक्रो एटीएम के उपयोग पर प्रकाश डाला। चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री अमूल्य रांहणेकर ने रिजर्व बैंक और नाबार्ड की गाइड लाइन के तहत अपेक्स बैंक, जिला बैंक व समितियों की वित्तीय कार्यप्रणाली में सावधानी रखने के लिये विभिन्न तकनीकी जानकारी पर मार्गदर्शन दिया। बैठक का संचालन उप महाप्रबंधक श्री के.टी.सज्जन एवं प्रबंधक श्री करुण यादव ने किया।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वश्री अम्बरीष वैद्य, अरुण मिश्र, अरविन्द बौद्धआर.एम. मिश्र और सुश्री कृति सक्सेना ने भी मार्गदर्शन दिया। बैठक में नवाचार के अनेक विषयों पर कुछ वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई गई। बैठक में सहकारिता विभागअपेक्स बैंक एवं 38 जिला बैंकों के अधिकारी उपस्थित हुए।

कृषि विज्ञान केंद्र, छतरपुर में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन

नौगांव। कृषि विज्ञान केंद्र, नौगांव (छतरपुर) में उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित दो दिवसीय बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को उन्नत उद्यानिकी तकनीकों, फसल प्रबंधन एवं नवीन कृषि विधियों की जानकारी प्रदान करना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन – कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिकडॉ. वीणापाणि श्रीवास्तवने की।

विशेष अतिथि – मुख्य अतिथिजनपद सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति के सदस्य श्री राजू यादवरहे।

तकनीकी सत्र – डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक, उद्यानिकी) – नर्सरी प्रबंधन, टिशू कल्चर, ग्रीनहाउस खेती, फल-फूल-सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त मौसम एवं सिंचाई प्रबंधन की जानकारी दी।

डॉ. बी. पी. सूत्रकार (परियोजना संचालक, आत्मा) – कृषि योजनाओं एवं किसानों के लिए सामयिक सलाह प्रदान की।

हेमंत कुमार सिन्हा (मौसम वैज्ञानिक) – जलवायु परिवर्तन का बागवानी फसलों पर प्रभाव एवं बचाव रणनीतियों पर प्रकाश डाला।

रोहित कुमार मिश्रा (एसआरएफ, निक्रा परियोजना) – जलवायु अनुकूल बागवानी तकनीकों एवं औषधीय-सुगंधित पौधों की खेती पर जानकारी दी।

श्री चितरंजन चौरसिया (प्रगतिशील किसान) – जैविक खाद बनाने की विधियों की व्याख्या की।

वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारीश्री योगेश यादव, श्री शैलेन्द्र यादव एवं श्री रजनीश परसरिया ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

प्रदर्शनी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण

किसानों कोनर्सरी इकाई, औषधीय एवं सगंध प्रदर्शन इकाई, फल उद्यान उत्पादन इकाईसहित कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण कराया गया।

ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग तकनीक, हाई-डेंसिटी प्लांटेशन एवं ग्राफ्टिंग तकनीकका प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया।

प्रशिक्षण में सहभागिता एवं प्रभाव

इस प्रशिक्षण मेंजिले के 8 विकासखंडों से 300 से अधिक कृषक एवं महिला किसानशामिल हुए।

अन्य गणमान्य व्यक्तियों मेंरिटायर्ड कृषि विकास अधिकारी श्री जी.डी. कोरी, सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार, श्री शिरीष पुरोहित (प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव), विकासखंड तकनीकी प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार अहिरवार, सहायक तकनीकी प्रबंधक श्री राहुल तिवारी एवं श्रीमती नेहा पाठकसहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को नवीनतम बागवानी तकनीकों, जल प्रबंधन, जैविक खेती एवं रोग-कीट नियंत्रण पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे जिले में उन्नत बागवानी तकनीकों के प्रति रुचि बढ़ेगी एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि विज्ञान केंद्र, छतरपुर किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

किसानों के कल्याण के लिये कृत संकल्पित म.प्र. सरकार

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसानों के कल्याण के लिये कृत संपल्पित होकर कार्य कर रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान (GYAN) से ध्यान पर फोकस करते हुए 4 मिशन के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। जल्द ही प्रदेश में किसान कल्याण के लिये मिशन भी प्रारंभ होने वाला है। वर्तमान में किसानों के कल्याण की विभिन्न योजनाएँ संचालित हो रही है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में 4 लाख रूपये की सहायता

प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत कृषकों को आंशिक अपंगता के लिये 50 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी अपंगता पर एक लाख रूपये एवं मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये प्रदान किये जाते है। साथ ही अंत्येष्टि के लिये 4 हजार रूपये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों

में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति व्यय एवं प्रसूति अवकाश सहायता, विवाह के लिये सहायता, प्रावीण्य छात्रवृत्ति सहायता, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना में स्थायी अपंगता सहायता, मृत्यु सहायता, अंत्येष्टि सहायता, मण्डी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना में सहायता आदि का समावेश किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री कृषि उपज मण्डी हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना-2015 लागू की गई। यह योजना उन हम्माल एवं तुलावटियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों पर प्रभावी होगी, जो मण्डी उपविधि के प्रावधान अनुसार मण्डी समिति में 18 से 55 वर्ष आयु के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी हैं।

योजनांतर्गत हितग्राही को न्यूनतम एक हजार एवं अधिकतम 2 हजार रूपये तक प्रति वर्ष अंशदान जमा करना होगा। इस योजना का लाभ पात्रता रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण या हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु/स्थायी अपंगता/ असाध्य बीमारी होने की दशा में प्राप्त होगा।

कृषि विपणन पुरुस्कार योजना

प्रदेश में मण्डियों में प्रत्येक वर्ष में 2 बार नर्मदा जयंती एवं बलराम जयंती के अवसर पर लॉटरी पद्धति द्वारा ड्रा निकाले जाते हैं, जिसमें बम्पर ड्रा के पुरुस्कार में "क" प्रवर्ग की मण्डी समिति में 35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर एवं "ख", "ग" तथा "घ प्रवर्ग की मण्डी समितियों में 50 हजार रूपये मूल्य तक के कृषि यंत्र दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मण्डी के श्रेणी अनुसार एक हजार से 21 हजार रूपये तक की नगद राशि के रुप में पुरुस्कार दिये जाते हैं।

कृषकों को 5 रुपये में भोजन थाली उपलब्ध कराने की योजना

प्रदेश में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की 257 मण्डी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिये आये कृषकों को 5 रुपये में भोजन थाली (न्यूनतम अनिवार्य मीनू 6 पूड़ी अथवा 6 रोटी, दाल एवं सब्जी के साथ) उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई।

गांधी शिल्प बाजार 2025 का भव्य समापन

उज्जैन। उज्जैन के अभिनंदन परिसर, देवास रोड पर आयोजित गांधी शिल्प बाजार 2025 का भव्य समापन हो गया। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस शिल्प मेले ने देशभर के शिल्पकारों और हस्तशिल्प प्रेमियों को एक मंच प्रदान किया।

कारीगरों और ग्राहकों में उत्साह

31 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक चले इस मेले में देशभर से आए लगभग 100 शिल्पकारों ने भाग लिया और अपने हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया। जरी वर्क, चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां, भागलपुरी और कश्मीरी सिल्क, लकड़ी के खिलौने, बांस फर्नीचर, आगरा का मार्बल क्राफ्ट, भदोही के कालीन, पश्मीना शॉल, फुलकारी वर्क, नागालैंड के ड्राई फ्लावर और पश्चिम बंगाल की जामदानी साड़ियों जैसे विभिन्न राज्यों के पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र रहे |

शिल्पकारों को मिला आर्थिक संबल

गांधी शिल्प बाजार ने देशभर के शिल्पकारों को अपने उत्पादों की सीधी बिक्री का एक सशक्त मंच प्रदान किया। ग्राहकों की भारी भीड़ के चलते कई शिल्पकारों ने अपने पूरे स्टॉक की बिक्री कर ली, जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ मिला।

उद्घाटन अवसर पर गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति

गांधी शिल्प बाजार 2025 के उद्घाटन अवसर पर नगर पालिका निगम की सभापति श्रीमती कलावती यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में एम. प्रभाकरण (क्षेत्रीय निदेशक, हस्तशिल्प, मुंबई), श्रीमती अर्पणा देशमुख (सहायक निदेशक, हस्तशिल्प, इंदौर), संजय कुमार सिंह (महाप्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ, भोपाल) और दिलीप मरमट (प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर) शामिल हुए । सभी अतिथियों ने इस आयोजन को कारीगरों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और इसे भविष्य में भी जारी रखने पर जोर दिया।

जनता ने मेले को सराहा

स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने इस मेले में बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी पसंद के हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी की। इस दौरान ग्राहकों ने कहा कि यह मेला न केवल देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कारीगरों को आर्थिक मजबूती भी प्रदान करता है।

सफल आयोजन के लिए आभार

गांधी शिल्प बाजार के आयोजन से जुड़े अधिकारियों और कारीगरों ने इसके सफल समापन पर संतोष व्यक्त किया। आयोजकों ने सभी कारीगरों, आगंतुकों और प्रशासन का आभार प्रकट किया और भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों की प्रतिबद्धता जताई।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज की छूट

भोपाल : एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। इस योजना के माध्यम से कृषक, कृषि अवसंरचना निर्माण के लिये बैंक से प्राप्त राशि रुपये 2 करोड़ तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ सात वर्षों के लिए से सकते है।

इस योजना के अंतर्गत वेयरहाउस, साइलोस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाई, प्राथमिक प्र-संस्करण इकाई, एयरोफोनिक फार्मिंग, हायड्रोफोनिक फार्मिंग, वर्टिकल कार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग के लिये अवसंरचना निर्माण की जा सकती हैं।

योजनांतर्गत मध्यप्रदेश को वर्ष 2025-26 तक 7440 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया है। जिसके विरुद्ध 7,804 करोड़ रूपये के कुल 10.860 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त कुल 10.047 प्रकरणों में 5978 करोड़ रूपये का डिसबर्समेंट किया जा चुका है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश को 500 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 1240 करोड़ रूपये के कुल 2152 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके हैं जो कि आवंटित लक्ष्य का 248 प्रतिशत है। साथ ही कुल 1745 प्रकरणों में 721 करोड़ रूपये का डिसबर्समेंट किया जा चुका है।

केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांशी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में "अवार्ड" से सम्मानित भी किया गया है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)

नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से सहकारिता मंत्रालय ने एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत तीन नई राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों की स्थापना की है:

- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल),
- नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल),
- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल)।

सभी स्तरों की सहकारी समितियाँ जो उपरोक्त प्रत्येक समिति के लिए निर्दिष्ट गतिविधियों में रुचि रखती हैं। विवरण निम्नानुसार है:

1. **राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल):** एनसीईएल को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषि सहकारी, भारतीय विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा बढ़ावा दिया गया है, ताकि सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं के अधिशेष वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जा सके, जिसमें प्रचारात्मक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। अब तक 8,863 सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी हैं।

   देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एनसीईएल द्वारा की गई पहल:

   i. एनसीईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 4,121 करोड़ रुपये मूल्य की 36 कृषि वस्तुओं का 10,42,297.81 एमटी निर्यात किया है।
   ii. एनसीईएल ने 26.40 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी सदस्य सहकारी समितियों को चुकता शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित किया है।
   iii. एनसीईएल ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के ऐसे उत्पादों की पहचान करने के लिए संपर्क किया है, जिनका वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक लाभ है, जिन्हें एनसीईएल के माध्यम से निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही, एक उपयुक्त एजेंसी को नामित करने के लिए भी कहा है, जो एनसीईएल के साथ राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।

2. **नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल):** एनसीओएल को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), जीसीएमएमएफ, नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा बढ़ावा दिया गया है ताकि एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाएं, पीएसीएस/एफपीओ सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक उत्पादों के विपणन के लिए संस्थागत समर्थन प्रदान किया जा सके। एनसीओएल विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा जैविक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों के विपणन में मदद करेगा। अब तक 5,184 सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन चुकी हैं।

   देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एनसीओएल द्वारा की गई पहल:

   i. एनसीओएल ने दिल्ली एनसीआर में जैविक खाद्य पदार्थों के लिए सफल आउटलेट्स के माध्यम से 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड लॉन्च किया है और सफल रिटेल स्टोर्स और अन्य मार्केट चैनलों में आटा, दालें, स्वीटनर और मसालों सहित 20 जैविक उत्पाद पेश किए हैं।
   ii. एनसीओएल ने उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड (यूओसीबी) के साथ समझौताज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और उत्तराखंड से 40 मीट्रिक टन प्रीमियम ऑर्गेनिक बासमती धान की खरीद की है। किसानों को बाजार मूल्य से 5 रुपये प्रति किलोग्राम अधिक प्रीमियम मिला।
   iii. एनसीओएल ने चालू रबी सीजन के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ से जैविक प्रमाणित तुअर (अरहर) की खरीद शुरू की है, जिसमें सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा शुल्क के साथ-साथ 5 रुपये प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त प्रीमियम भी दिया जा रहा है।
   iv. एनसीओएल ने प्रमाणित जैविक उत्पादों की खरीद के लिए 8 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और 24 अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए नोडल एजेंसियों की पहचान की है।
   v. एनसीओएल ने एपीडा के साथ मिलकर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत सहकारी समितियों को कानूनी इकाई के रूप में शामिल किया है।

3. **भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल):** बीबीएसएसएल को इफको, कृभको, नेफेड, एनडीडीबी और एनसीडीसी द्वारा सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण करने के लिए बढ़ावा दिया गया है ताकि फसल की पैदावार में सुधार हो और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित की जा सके। बीबीएसएसएल सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब तक 17,425 सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं।

   देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए बीबीएसएसएल द्वारा की गई पहल:

   i. बीबीएसएसएल निजी सहित सभी उपलब्ध विपणन चैनलों के माध्यम से 'भारत बीज' के वितरण के लिए खुदरा दुकानें स्थापित कर रहा है।
   ii. रबी 2023-24 सीजन के दौरान 11,575.45 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन किया गया।
   iii. खरीफ 2024 सीजन के दौरान 3,820 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन किया गया।
   iv. रबी 2024 सीजन के दौरान, बीबीएसएसएल ने 6 राज्यों में 5,596 हेक्टेयर क्षेत्र में 8 फसलों की 49 किस्मों की बुवाई की है, जिससे लगभग 1,64,804 क्विंटल आधारभूत और प्रमाणित बीजों का उत्पादन हुआ है।
   v. बीबीएसएसएल को अब तक 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लाइसेंस प्राप्त हो चुका है।

सरकार ने 15.02.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में अगले पांच वर्षों में वंचित क्षेत्रों सहित देश के सभी पंचायतों/गांवों को शामिल करते हुए नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा।

योजना के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के समन्वय से 19.9.2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) शुरू की है, जिसमें संबंधित सभी हितधारकों के लिए लक्ष्य और समयसीमा का संकेत दिया गया है। मार्गदर्शक के अनुसार, योजना का जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार इस पहल के शुभारंभ के बाद से अब तक देश में 3,654 नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, 8,256 डेयरी और 990 मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पीएसीएस को ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। यह सामान्य ईआरपी सॉफ्टवेयर परियोजना के अंतर्गत देश भर के सभी पीएसीएस को प्रदान किया गया है ताकि पीएसीएस की सभी कार्यात्मकताओं, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट दोनों पर डेटा एकत्र किया जा सके। यह सॉफ्टवेयर राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन योग्य है।

ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से पीएसीएस के प्रदर्शन में दक्षता लाता है। इसके अलावा, पीएसीएस में शासन और पारदर्शिता में भी सुधार हुआ है, जिससे ऋणों का तेजी से वितरण, लेन-देन की लागत में कमी, भुगतान में असंतुलन में कमी, डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ निर्बाध लेखांकन हुआ है।

कुल 50,455 पीएसीएस को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है तथा 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर खरीदा गया है।

जैविक एवं प्राकृतिक खेती में प्रदेश को अग्रणी बनाने के प्रयास

भोपाल :प्रदेश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। खेती की इस पद्धति को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए क्लस्टर स्थापित करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मध्यप्रदेश जैविक खेती में अग्रणी रहे। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जैविक एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में रेशम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन का भी कार्य किया जा रहा है। कृषकों को जैविक खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में जैविक खेती का क्षेत्रफल देश में सबसे अधिक है। मंडला, डिण्डोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर जिले में जैविक खेती प्रमुखता से की जा रही है।

राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सहकारिता विभाग को कृषि एवं उद्यानिकी के साथ सम्बद्ध किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा प्राकृतिक खेती पर काम किया जा रहा है।

किसानों की समृद्धि के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम

अगले पाँच वर्षों में कृषि निर्यात को दोगुना किया जायेगा। अगले पाँच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी को और अधिक बढ़ाया जायेगा। उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान की स्थापना, दाल की प्रोसेसिंग एवं वेल्यू चेन को बढ़ावा दिया जायेगा, डिण्डोरी में श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना, प्रदेश में श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी के माध्यम से प्रचार-प्रचार, प्रदेश में 10 सोयाबीन विशिष्ट एफपीओ का गठन किया जा रहा है। मिशन दाल के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में दाल का उत्पादन बढ़ाया जायेगा, प्रदेश में भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल संचालित की जा रही है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा "स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता" अभियान के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत सहकारिता के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

माननीय सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार, 13 फरवरी 2025 को सभी सहकारी संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों में स्वच्छता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत, कार्यालयों को सुव्यवस्थित करने, पुराने रिकॉर्ड को सहेजने, इंडेक्स रजिस्टर के संधारण, शौचालयों की सफाई तथा कार्यस्थल को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए गए।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा इस आदेश के परिपालन में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर –

- कार्यालय दस्तावेजों को सुव्यवस्थित किया गया।
- पुराने रिकॉर्ड की छंटाई एवं संधारण किया गया।
- कार्यालय कक्षों एवं शौचालयों की विशेष सफाई की गई।
- कार्यालय परिसर को सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाया गया।

इस स्वच्छता अभियान में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल के अधिकारी-कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी ने मिलकर स्वच्छ, व्यवस्थित एवं अनुशासित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस पहल के माध्यम से सहकारिता के मूल्यों को मजबूत करने एवं कार्यस्थलों को स्वच्छ और सुसंगठित बनाए रखने का संदेश दिया गया।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों एवं सहकारिता विभाग में स्वच्छता अभियान

भोपाल। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने और कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों एवं सहकारिता विभाग के विभिन्न कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत प्रदेशभर के कई प्रशिक्षण केंद्रों एवं कार्यालय परिसरों में सफाई कार्य संपन्न हुआ।

नौगांव सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में व्यापक सफाई अभियान

नौगांव स्थित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में स्वच्छता अभियान के तहत प्राचार्य कक्ष, व्याख्याता कक्ष, लेखा कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष सहित पूरे परिसर की सफाई की गई। इसके अतिरिक्त सड़क एवं प्राचार्य निवासके आसपास भी सफाई अभियान चलाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

इंदौर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में सफाई अभियान

इंदौर स्थित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में प्रांगण, कार्यालय कक्ष, फर्नीचर एवं उपकरणों की विशेष सफाई की गई। प्रशिक्षण केंद्र के समस्त स्टाफ ने इसमें भाग लिया और पूरे परिसर को स्वच्छ बनाया गया।

भोपाल, खंडवा और धार में भी सफाई अभियान सक्रिय

भोपाल स्थित संघ सहकारी प्रशिक्षण केंद्रमें भी यह अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया, जिसमें कार्यालय कक्ष एवं परिक्षेत्र की सफाई की गई। खंडवा जिले में भी इसी तरह कार्यालय एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ किया गया। धार जिले मेंकार्यालय के इंडेक्स रजिस्टरों के संधारण के साथ-साथ सफाई अभियान भी चलाया गया, जिससे सभी दस्तावेज व्यवस्थित हो सके।

ग्वालियर सहकारिता विभाग में भी चला अभियान

ग्वालियर के सहकारिता विभाग कार्यालय में स्टाफ ने सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरे कार्यालय परिसर की सफाई की। कार्यालय में रखे फाइलों, दस्तावेजों एवं अन्य जरूरी सामग्रियों को सुव्यवस्थित किया गया, जिससे स्वच्छ और व्यवस्थित कार्य वातावरण तैयार किया जा सके।

स्वच्छता अभियान का उद्देश्य एवं सफलता

इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य न केवल कार्यालय परिसरों को स्वच्छ बनाना था, बल्कि कर्मचारियों और अधिकारियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी था। सभी प्रशिक्षण केंद्रों और सहकारिता कार्यालयों में इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है, जो यह दर्शाता है कि सरकारी एवं सहकारी संस्थान भी स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस तरह के प्रयासों से कार्यस्थलों पर न केवल स्वच्छ वातावरण बनेगा बल्कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।